Investigations as called for, are being made. Assessment of the Company for the assessment year 1973-74 has already been reopened.

(b) Mrs. Indira Gandhi and S/Shri Rajiv Gandhi and Sanjay Gandhi are assessed to wealth-tax. Requisite enquiries are being made in their cases.

बिड़ला बन्धुओं के मामले में कर निर्धारण

3786. **श्री हुकम देव नारायण यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिड़ला बन्धुओं के मामले में कर निर्धारण का पुनर्विलोकन प्रतिवर्ष किया जाता है तथा क्या तकनीकी अधिकारियों, विभागीय अधिकारियों और न्यायिक मजिस्ट्रेटों की एक समिति ने उनकी चल तथा अचल सम्पत्ति, भवनों और उनके द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं तथा विदेशों में उनकी कपनियों की सम्पत्ति का कभी निर्धारण किया है तथा क्या सरकार का विचार ऐसी जांच करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : बिड़ला समूह के प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी मामलों की जांच का कार्य निरीक्षण निदेशालय (जांच) में विशेष कक्ष द्वारा समन्वित किया जा रहा है । आय-कर तथा धन-कर, कर-निर्धारण वर्ष के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं । यदि उपलब्ध सामग्री न्यायोचित ठहराती है तो पूरे किये गये कर-निर्धारणों के बारे में नये सिरे से कर-निर्धारण करने के लिये फिर से कार्यवाही की जाती हैं । इस प्रकार इन मामलों की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

बिड़ला समूह के मामलों के प्रत्यक्ष कर निर्धारणों के सम्बन्ध मे तकनीकी अधिकारियों विभागीय अधिकारियों और न्यायिक मजिस्ट्रेटों की किसी समिति का गठन नहीं किया गया है । इस प्रकार समिति का गठन करने के लिये प्रत्यक्ष कर अधिनियमों में कोई उपबन्ध नहीं है ।

Violation of Stamp Acts in Gujarat and Maharashtra

3787. SHRI VIJAY KUMAR N. PATIL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some of the agencies in Gujarat and Maharashtra are instigating Adivasis to violate the Stamp Acts;

(b) whether it is a fact that in certain transactions (sale deeds) of land or other property, currency notes and coins are affixed on the stamp papers; and

(c) if so, what action the Government has proposed to stop the spread of such illegalities?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) to (c). The administration of Stamp Act vests in the State Governments. The information has been called for from the Governments of Gujarat and Maharashtra and will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

मानक गैस स्टोवों का निर्माण

2788. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस स्टोवों के लिये कोई मानक निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्धारित मानक से निर्मित किये गये स्टोव ही, इसके लिये लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर बाजार में बेचे जा सकते हैं अथवा किसी भी मानक से निर्मित गैस स्टोवों को बेचने के लिये सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में पूरी जानकारी क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (ग). भारतीय मानक संस्था ने आई० एस० : 4246--1972 प्रकाशित किया है, जिसमें घरेलू गैस स्टोव के लिए मानक निर्धारित किए है । तथापि, ये स्वैच्छिक हैं, अनिवार्य नहीं । सरकार ने गैस स्टोव का मूल्य नियत नहीं किया है ।

आय में असमानता और आर्थिक विषमता दूर करना

3789. **श्री रामलाल राही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय में समानता लाने तथा आर्थिक विषमता दूर करने के कुछ ठोस प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). वर्तमान सरकार की नीति यह है कि रोजगार के अवसरों को विशेषत: ग्रामीण